



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1990/वौष 29, 1911

No. 30]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1990/PAUSA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त संचालय
(प्रशासनिक कार्य विभाग)
(वैकीय प्रभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1990

का. आ. 31(अ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1919 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (यख) के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए आदेश पत्र पर विचार करने के बाद बांद्रा पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक लि. बांद्रा, बम्बई-400050 (जिसे इसके पश्चात् 'महकारी बैंक' कहा गया है) के संबंध में एनर्द्ध द्वारा 19 जनवरी, 1990 को बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर 19 मई, 1990 तक और उस दिवस को मिला कर अधिस्थगन आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान महकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों का गण किया जाता अथवा शुरू की गई कार्यवाहियों को जारी रखना रोकित किया जाता है, किन्तु यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बॉम्बार्डमेंट

अधिनियम 1960 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

2. केन्द्रीय सरकार, एनर्द्ध द्वारा यह निवेदन देती है कि स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान यह महकारी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अधिम नहीं देगा, किसी अधिम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिस्थिति का अन्य संक्रमण अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार या वाणिज्य स्वीकार नहीं करेगा, कोई निवेदन नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों के संबंध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं करेगा अथवा अदायगी करेगा, स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझौता अथवा टहाराव नहीं करेगा किन्तु यह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित गोमा तक यथावश्यक अदायगियां अथवा खर्च करेगा :

(1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा बालू खाते अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते की शेष रकम में से 250 रुपये से अधिक राशि, जिसमें 26 दिसम्बर, 1987 के बाद भुगतान की गई राशि यदि कोई हो, शामिल है, करने हुए बराबर कि अदा की गई रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राशि 250/- रुपये से ज्यादा न हो।

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो;

(2) ऐसे किसी बैंक द्वारा, ऐसी प्रत्येक अवधि के लिए जो सहकारी बैंक द्वारा 26 दिसम्बर 1987 को जारी कर दिए गए हैं, और जिसका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी अधिस्थान आदेश लागू होता है।

(3) 26 दिसम्बर, 1987 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राशि वाले वे उस तारीख से पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गई हों।

(4) ऐसा कोई व्यय जो किसी सहकारी बैंक के द्वारा उसके अथवा उसके विरुद्ध दायां किए गए मुकदमे, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध की गई डिब्री या बैंक की मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना आवश्यक हो, वगैरह कि प्रत्येक मुकदमे, अपील अथवा डिब्री के संबंध में किए जाने वाले व्यय की रकम 600/- रुपये से अधिक हो, तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का लिखित अनुमति ली जाएगी;

(5) ऐसा कोई व्यय जो ब्रिडो, बीमा और प्रत्येक गारंटी निगम को वेय प्रोमिसम की राशि हो; और

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यव सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करना अनिवार्य हो।

वगैरह कि जहां किसी एक कैलेण्डर साल में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थान आदेश से पहले के छः कैलेण्डर महीनों में उस मद पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो, अथवा उसे अधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250/- रुपये से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी।

3. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह भी निवेदन देती है कि सहकारी बैंक की सर्वोच्च अधिस्थान की अधि के दौरान:

(क) यह सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगियां कर, सकेत अथवा सहकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार अथवा महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि. या टाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. टाणे अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को किए गए ऋणों अथवा अधि, जो अधिस्थान आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाए जाने में थे, की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक हो।

(ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगियां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खाने चलाने की अनुमति दी जाएगी।

परंतु इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि इस बैंक सहकारी को किसी रकम के लिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि. अथवा बैंक किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपने आपकी आवश्यकता करना होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गई शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) यह सहकारी बैंक, उन हुंडियों को, जो वसूल न की गई हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर मौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई अधिभार अथवा हक न हो अथवा बैंक हुंडियों में उसका कोई हिस्सा न हो।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों को जो इस बैंक के पास किसी ऋण, नकदी, कर्ज अथवा ओवर ट्राफ्ट के बदले गिरवी, धर्मपत्र अथवा बंधक रखा गई हो अथवा अथवा प्रभावित की गई हो निम्नलिखित मामलों में छोड़ अथवा दे सकता है:

(1) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थिति ऋणकर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है; और

(2) किसी अन्य मामले में, उन सीमा तक जो रकम जितनी आवश्यक अथवा सम्भव हो, निविष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधिस्थान आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भा उर्वे हों, उस माल और प्रतिभूतियों पर माजिन के अनुपातों को कम किए बिना।

[एफ. सं. 6-4/89-ए. सी.]

प्रवीण कुमार तेजपान, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 19th January, 1990

S.O. 51(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45, read with clause (zb) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Bandra People's Co-operative Bank Ltd., Bandra, Bombay-400 050 (hereinafter referred to as the Co-operative Bank) for the period from close of business on the January 19, 1990 upto and inclusive of the May 19, 1990 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the said Bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder:—

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account, by whatever name called, a sum not exceeding Rs. 250 including the amount, if any, paid after 26th December, 1987.

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 250;

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued on or before 26th December 1987 by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) The amounts of the bills received for collection on or before 26th December 1987 whether realized before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it;

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 600/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred;

- (v) the amount of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and
- (vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co-operative Bank;

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that, during the period of moratorium granted to it, the Co-operative Bank—

- (a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying

loans or advances granted against Government securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Bombay District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

- (b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid;

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

- (c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;
- (d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—
 - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and
 - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 6-4/89-AC]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

